संसद से 'टपोरी' तक: जब राजनीति में आया 'बम्बइया' अंदाज

ऑफ द रिकॉर्ड

भारतीय राजनीति ने कुछ समय के लिए मुंबई की सड़कों वाली भाषा का रुख किया, जब कंगना रनौत ने राहुल गांधी को 'टपोरी' कह दिया- यह एक ऐसा शब्द है जो संसदीय चर्चाओं की बजाय बॉलीवुड की बातचीत में ज्यादा फबता है। इस टिप्पणी ने कई लोगों को चौंका दिया, खासकर इसलिए क्योंकि 'टपोरी' शब्द आमतौर पर राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा नहीं होता। जो लोग इस शब्द से परिचित नहीं हैं, उनके लिए इसका मोटा-मोटा मतलब है- सड़कों पर रहने वाला एक चतुर और बेफिक्र इंसान; जो थोड़ा शरारती हो, थोड़ा दिलकश हो, और कभी-कभी किसी फिल्मी हीरो जैसा लगे। इसे सरकारी नीतियों वाले कागजों की तरह कम और फिल्म 'रंगीला' वाली ऊर्जा की तरह ज्यादा समझिए।

जैसा कि उम्मीद थी, इसका विरोध तुरंत शुरू हो गया। कांग्रेस ने इसे नजरअंदाज कर दिया लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने एक तीखा जवाब देते हुए इस टिप्पणी को गलत बताया और आलोचकों को गांधी के महिला मुद्दों पर सार्वजनिक रुख की याद दिलाई-साथ ही उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि ऐसे वंश से आने वाले किसी शख्स को निशाना बनाया जा रहा है, जो अपनी महिला नेताओं के लिए जाना जाता है।

लेकिन असली दिलचस्पी भाषा से जुड़ी है। 'टपोरी' शब्द, जिसकी जड़ें मराठी की गली-मोहल्लों वाली संस्कृति में हैं, कभी मुंबई की 'टपरियों' (चाय की दुकानों) के आस-पास घूमने वाले, शोखी भरे और शरारती नौजवानों के लिए इस्तेमाल होता था। समय के साथ, बॉलीवुड ने इस शब्द को थोड़ा तराशा और इसे कुछ ऐसा बना दिया जिसकी लोग चाहत करने लगे-बगावती अंदाज वाले 'कूल' होने का एक तमगा। शायद इसी वजह से यह भ्रम पैदा होता है।

क्या यह कोई अपमान है, किसी का मजाक उड़ाना है, या फिर अनजाने में की गई कोई तारीफ? आज की राजनीति में, गली-मोहल्लों में बोले जाने वाले शब्द भी कुछ समय के लिए पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं।

'होर्मुज जलडमरूमध्य' पर ईरानी नियंत्रण के बाद अमरीका का रुख और कड़ा

बेरूत: इसराईली हमले में तबाह हुई इमारत के मलबे पर से गुजरता व्यक्ति।

ईरान जंग में मारे जाने वाले प्रमुख नेता/अधिकारी

अयातुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर | अली लारीजानी, ईरान सिक्योरिटी काउंसिल चीफ | अली शामखानी, खामेनेई के करीबी सलाहकार | मोहम्मद पाकपुर, आई.आर.जी.सी. चीफ | अजीज नसीर जादेह, रक्षा मंत्री | अब्दुलरहीम मौसवी, आर्मी चीफ | गुलामरजा सुलेमानी, बसीज फोर्स कमांडर

दुबई, 26 मार्च (प.स.): पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के लिए राजनयिक प्रयास बृहस्पतिवार को विफल होते दिखे क्योंकि ईरान और अमरीका ने अपने रुख को और कड़ा कर लिया।

तेहरान ने महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण को औपचारिक रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया, जबकि वाशिंगटन ने क्षेत्र में अमरीकी सैनिकों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी, जिनका उपयोग ईरान में जमीनी कार्रवाई के लिए किया जा सकता है।

अमरीकी पोत 'यू.एस.एस. त्रिपोली' लगभग 2500 नौसैनिकों के साथ पश्चिम एशिया की ओर बढ़ गया है। साथ ही, 82वीं एयरबोर्न बटालियन के कम से कम 1000 सैनिकों को भी इस क्षेत्र में भेजा गया है। मौजूदा हालात में ऐसा माना जा रहा है कि अमरीका का ध्यान संभवत: खार्ग द्वीप पर स्थित ईरान के तेल टर्मिनल या जलडमरूमध्य के पास के अन्य स्थलों पर नियंत्रण हासिल करने पर केंद्रित है। अमरीकी नौसेना के एडमिरल ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में अमरीकी बल अब तक 10,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले कर चुके हैं।

ईरान की समाचार एजैंसियों- फार्स और तसनीम ने सांसद मोहम्मदरेजा रेजाई कूची के हवाले से कहा कि संसद जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने देने के लिए शुल्क लगाने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इसको (जहाज) सुरक्षा प्रदान करते हैं और यह स्वाभाविक है कि जहाज और तेल टैंकर इसके लिए शुल्क चुकाएं।

अमरीका का आरोप-ईरान को खतरनाक ड्रोन दे रहा रूस

युद्ध में ईरान को रूस मजबूत कर रहा है। रूस ईरान को घातक ड्रोन और हथियार देने जा रहा है। तनाव के बीच कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है। दावे-प्रतिदावे के बीच क्रेमलिन ने गुरुवार को उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि रूस ईरान को हमलावर ड्रोन भेजने की तैयारी कर रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इसे मीडिया द्वारा फैलाई जा रही 'झूठी खबरों' में से एक बताया और लोगों से अपील की कि ऐसी रिपोर्टों पर ध्यान न दें।

कहा जा रहा है कि अगर फाइनैंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह मध्य पूर्व के चल रहे संघर्ष में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस तेहरान को गेरान-2 और शाहेद-136 जैसे आत्मघाती ड्रोन की आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा है, जो ईरान के स्वदेशी शाहेद प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

ट्रम्प ने नाटो सहयोगियों को फिर सुनाई खरी-खोटी

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर नाटो सहयोगियों पर गुस्सा जाहिर किया है। यह पहली बार नहीं है, जब ट्रम्प ने नाटो के सदस्य देशों के खिलाफ गुस्सा जताया है इससे पहले भी उसने इन देशों को कायर कहते हुए चेतावनी दी थी कि उनका यह रवैया भुलाया नहीं जाएगा।

अमरीका के समयानुसार गुरुवार सुबह करीब 6 बजे ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नाटो देशों को खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, "नाटो देशों ने ईरान जैसे 'पागल देश', जो अब सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है, के खिलाफ मदद के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया। अमरीका को नाटो से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इस महत्वपूर्ण समय को कभी मत भूलना।"

युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत को लेकर गंभीर हो ईरान : ट्रम्प

ट्रम्प ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर कहा कि ईरानी नेताओं को 'बहुत देर होने से पहले बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा हो जाने पर, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा।'

यह पोस्ट ट्रम्प के उस बयान के एक दिन बाद की गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देश समझौते के करीब हैं। ट्रम्प ने बृहस्पतिवार को फिर कहा कि अमरीका द्वारा प्रस्तावित 15 सूत्री युद्धविराम योजना को ईरान द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद तेहरान 'हमसे समझौता करने की भीख मांग रहा है।'

नेतन्याहू बोले-ईरान पर लगातार हमले जारी

इसराईल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना ईरान के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। उन्होंने दावा किया कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नौसेना कमांडर को मार गिराया गया नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसराईल ईरान के आतंकी शासन के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई कर रहा है।

उन्होंने बताया कि बीती रात एक बड़े ऑप्रेशन में रिवोल्यूशनरी गाड्‌र्स के नौसेना कमांडर को खत्म किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कमांडर कई हमलों में शामिल था और होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की रणनीति का नेतृत्व कर रहा था। नेतन्याहू ने कहा कि यह कार्रवाई इसराईल और अमरीका के बीच सहयोग का उदाहरण है और दोनों देश मिलकर युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने में जुटे हैं।

पुतिन बोले-ईरान युद्ध से कोविड जैसे हालात का खतरा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मिडल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के असर का सटीक अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। जो लोग इसमें शामिल हैं वे भी इसके नतीजों का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कोविड-19 जैसी स्थिति आ सकती है।

मॉस्को में कारोबारियों से बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि यह जंग अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इसके साथ ही तेल-गैस, धातु और उर्वरक कंपनियों पर भी इसका दबाव बढ़ रहा है।

रूसी मालवाहक जहाजों को नौसैनिक सुरक्षा मुहैया कराएगा रूस

मास्को, 26 मार्च (प.स.): रूस ने कहा है कि वह अपने मालवाहक जहाजों को नौसैनिक सुरक्षा प्रदान करेगा क्योंकि पश्चिमी देशों की नौसेनाओं द्वारा ऐसे जहाजों को रोकने की घटनाएं बढ़ रही हैं। रूस के मैरीटाइम बोर्ड ने बुधवार को एक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर रूसी जहाजों की जब्ती या रोकथाम से निपटने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए।

ये दिशा-निर्देश मुख्य रूप से अजोव-काला सागर क्षेत्र और बाल्टिक सागर पर लागू होंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य क्षेत्रों में भी नौसैनिक सुरक्षा दी जाएगी या नहीं। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब यूरोपीय देश रूस के तथाकथित 'शैडो फ्लीट' को बाधित करने की कोशिशें तेज कर रहे हैं, जिनका उपयोग भारत और चीन जैसे पारंपरिक ग्राहकों तक हाइड्रोकार्बन पहुंचाने के लिए किया जाता है।

बोर्ड के प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव ने कहा, "रूस के साथ काम करने वाले जहाज मालिकों को नौसेना के साथ समन्वय के निर्देश दिए गए हैं और रूसी मालवाहक जहाजों की निगरानी बढ़ा दी गई है।" उन्होंने कहा कि जहाजों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रूसी नौसेना उनकी निगरानी करेगी और नौवहन क्षेत्रों पर नजर रखेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने घोषणा की है कि उन्होंने सेना को उन रूसी जहाजों को रोकने और तलाशी लेने की अनुमति दी है, जिन्हें उनकी सरकार प्रतिबंधों के बावजूद तेल निर्यात करने वाले नैटवर्क का हिस्सा मानती है।

बेरूत: इसराईली हवाई हमले के बाद एक गांव से उठता धुएं का गुबार।

ईरानी कमांडर बोले-हमारी जमीन का एक-एक इंच सुरक्षित

ईरान के एक सैन्य कमांडर ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अमरीका और इसराईल के लिए जमीनी युद्ध कहीं ज्यादा खतरनाक और महंगा साबित होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहानशाही ने कहा कि सीमाओं पर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और ईरान किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है।

जहानशाही ने कहा कि ईरान की जमीन का एक-एक इंच सुरक्षित है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब खबरें हैं कि ट्रम्प सरकार ईरान पर दबाव बनाने के लिए फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की सोच रही है ताकि होर्मुज को फिर से खोला जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने हाल के हफ्तों में खार्ग द्वीप पर अतिरिक्त सैनिक और एयर डिफैंस सिस्टम तैनात किए हैं और अपनी तैयारी बढ़ा दी है।

कानूनी पेशे में लैंगिक भेदभाव उजागर, 81 फीसदी महिला वकीलों ने करियर को बताया कठिन

नई दिल्ली, 26 मार्च (इंट): सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एस.सी.बी.ए.) द्वारा देशभर में किए गए सर्वे में सामने आया है कि 81 फीसदी महिला वकीलों का मानना है कि कानूनी पेशे में आगे बढ़ना पुरुषों की तुलना में अधिक कठिन है। इस सर्वे में 2604 महिला वकीलों ने हिस्सा लिया।

करियर को बताया ज्यादा चुनौतीपूर्ण

करीब 81.3% महिलाओं ने कहा कि उनका करियर पथ ज्यादा कठिन रहा, जबकि 41.1% ने इसे 'बहुत ज्यादा मुश्किल' बताया। वहीं 63.7% ने स्वीकार किया कि किसी न किसी समय यह पेशा उन्हें हतोत्साहित करता है। यह रिपोर्ट हाल ही में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा बेंगलुरु में एस.सी.बी.ए. के पहले सम्मेलन के दौरान जारी की गई। रिपोर्ट का शीर्षक 'डॉक्यूमैंटिंग वॉइसेज ऑफ वुमेन लीगल प्रोफैशनल्स इन इंडिया' है।

संरचनात्मक बाधाएं बनी बड़ी समस्या

सर्वे में बताया गया कि महिलाओं के सामने इन्फ्रास्ट्रक्चर, नैटवर्किंग, नेतृत्व तक पहुंच और वर्क-लाइफ बैलेंस जैसी कई बाधाएं हैं। 1923 के कानून के बावजूद आज भी जैंडर बायस, कमजोर मैंटरशिप और आर्थिक अस्थिरता जैसे मुद्दे करियर को प्रभावित कर रहे हैं।

प्रोफैशनल ग्रोथ में असमानता

53.9% का मानना है कि सीनियर डिजिग्नेशन पुरुषों के लिए आसान है, जबकि सिर्फ 1.7% ने कहा कि महिलाओं को फायदा मिलता है। 64.5% महिलाओं ने कभी सरकारी कानूनी पद नहीं संभाला और शीर्ष पदों पर महिलाओं की मौजूदगी बेहद कम है।

संसाधनों और अवसरों की कमी

केवल 19% के पास कोर्ट के पास ऑफिस हैं, जबकि 12% के पास अपना ऑफिस ही नहीं है। आर्थिक दबाव, महंगे किराए और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बड़ी बाधा हैं। करीब 75% महिलाओं को पेड लीगल डाटाबेस या क्लर्क की सुविधा नहीं मिलती। महिलाओं ने सीमित अवसर (60%), नैटवर्किंग में बाधा (42.8%), वेतन असमानता (40.2%) और वर्क-लाइफ असंतुलन (37.5%) को प्रमुख समस्याएं बताया। 84% महिलाओं ने पिछले एक साल में काम से जुड़े तनाव की बात कही।

उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाएं

करीब 16.1% महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की बात स्वीकार की, जबकि 12.7% ने इस पर जवाब नहीं दिया। इनमें से 57% को काम से बाहर करने या प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। वहीं 72.3% महिलाओं ने माना कि उनके जैंडर का नैटवर्किंग पर नकारात्मक असर पड़ा। सर्वे के अनुसार 5 साल तक के अनुभव वाली महिला वकील सबसे बड़ा वर्ग (37.4%) हैं। अधिकांश जिला अदालतों (52.9%) में प्रैक्टिस करती हैं, जबकि हाई कोर्ट (28.8%) और सुप्रीम कोर्ट (13%) में कम संख्या है।

परिवार और करियर का टकराव

71.5% महिलाओं ने कहा कि वैवाहिक स्थिति उनके करियर को प्रभावित करती है, जबकि 30.3% ने माना कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अवसर सीमित हो जाते हैं।

करीब 64.7% महिलाओं का मानना है कि बार लीडरशिप में उन्हें बराबर अवसर नहीं मिलते। हालांकि 76.4% महिलाएं न्यायपालिका की ओर रुख करने पर विचार कर रही हैं, जहां उन्हें ज्यादा स्थिरता दिखती है।

सुधार की जरूरत

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि महिलाओं को समान अवसर, बेहतर मैंटरशिप, आर्थिक सहायता, मातृत्व सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल और संस्थागत सुधार की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि यह डाटा स्वयं-रिपोर्टेड है, जिससे कुछ संवेदनशील मुद्दों की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाई हो सकती है। सर्वे ने साफ कर दिया है कि कानूनी पेशे में महिलाओं को आज भी कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। सुधारात्मक कदम उठाए बिना लैंगिक समानता हासिल करना मुश्किल होगा।

'ट्रांसवुमन' संग वीडियो पर विवाद, मंत्री झिरवाल के इस्तीफे की मांग तेज

मुंबई, 26 मार्च (प.स.): महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि विभाग के मंत्री नरहरी झिरवाल एक कथित वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विवादों में घिर गए हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे 'अश्लील एवं अनैतिक आचरण' बताते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वायरल वीडियो में झिरवाल अपने सरकारी आवास पर एक ट्रांसवुमन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। पार्टी ने इस घटना को राज्य की राजनीति में 'नैतिक पतन' का उदाहरण बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मामले को सत्तारूढ़ दलों के भीतर की खींचतान का परिणाम बताया। उनका कहना है कि यह 'सरकार के भीतर की गैंगवार' का हिस्सा हो सकता है, जहां सहयोगी दल एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं।

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि से नैतिक आचरण की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इस घटना ने सार्वजनिक जीवन की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से झिरवाल को तत्काल मंत्री पद से हटाने की मांग की।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बृजमोहन पुत्र स्वर्गीय कुलदीप निवासी वार्ड नं. 05, नजदीक ज्ञान चंद हलवाई, खरखौदा, तह. खरखौदा, जिला सोनीपत ने बयान किया है कि उसके पिता श्री कुलदीप के देहांत दिनांक 23.12.2017 के उपरांत उनकी संपति के 4 वैध वारिस 1. बृजमोहन (पुत्र) 2. सुदेश देवी (पत्नी) 3. भारती (पुत्री) 4. आरती (पुत्री) हैं। इनकी संपति की पुरानी प्रॉपर्टी आईडी संख्या 0193/5 व नई प्रॉपर्टी आईडी संख्या 7CEJF2M7, 7CO7VCM2 है। अतः यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त वारिसों या संपति के संबंध में कोई आपति हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर नगर पालिका कार्यालय, खरखौदा, जिला सोनीपत में लिखित रूप में अपनी आपति दर्ज करवा सकता/सकती है। निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपति प्राप्त न होने की स्थिति में उक्त संपति संबंधित वारिसों के नाम स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर दी जाएगी, जिसके लिए बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

कानूनी वारिस, सम्पदा अधिकारी की ओर से

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)

निविदा सूचना
(प्रकाश और ध्वनि उपकरण इत्यादि किराये पर उपलब्ध)

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला समय-समय पर अपने सदस्य राज्यों यानि **राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चण्डीगढ़** में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें देश के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकार प्रदर्शन करते हैं।

प्रतिष्ठित फर्मों/एजेंसियों जिनके पास राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक उत्सवों/त्यौहारों में काम करने का अनुभव, प्रमाणित रिकार्ड, पूर्ण तकनीकी ज्ञान, फेलप्रूफ दृष्टिकोण के साथ बिना किसी विघ्न के कार्य करने में सक्षम हो, से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए प्रकाश और ध्वनि उपकरण किराए पर लेने और संचालित करने के लिए निविदाएं (दो भागों में) - **भाग 1-तकनीकी बोली और भाग 2-मूल्य बोली** https://www.gerpegov.com/MOC पर आमंत्रित की जाती हैं। आयोजन स्थल पर स्थिति की तात्कालिकता के अनुसार उपकरणों की आवश्यकता और दिनों की संख्या अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न हो सकती है।

निविदाएं जिनमें तकनीकी बोली और मूल्य बोली शामिल है, निदेशक, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला को संबोधित की जानी चाहिए और https://www.gerpegov.com/MOC पर **14/04/2026 को शाम 05.00 बजे** तक अपलोड की जानी चाहिए, जोकि **15/04/2026. को दोपहर 03.00 बजे** खोली जाएगी। तकनीकी बोली में उनके कार्य अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण जिनमें भारत के विभिन्न राज्यों में कम से कम 3 सरकारी एजेंसियों के साथ कार्य करने के अनुभव के समर्थन में कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र; पिछले 3 वर्षो का आयकर रिटर्न; पंजीकृत संख्या; जीएसटी संख्या; पैन नंबर; कम से कम **रुपये 50.00 लाख** मूल्य के एक एकल कार्यक्रम के लिए लाइट और साउंड सेवाओं का निष्पादन, साथ में कार्य आदेश और समापन प्रमाण पत्र; और पिछले तीन वर्षो के दौरान कम से कम **रुपये 1.00 करोड़ प्रति वर्ष** का वित्तीय कारोबार होना भी शामिल होगा। केवल उन्हीं फर्मों/एजेंसियों की मूल्य बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी बोली की जांच में अर्हता प्राप्त करेंगी। फर्मों/एजेंसियों को निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में **रुपये 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये)** जमा करने होंगे। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मूल्य बोली प्रपत्र एवम् निविदा संबंधी अन्य जानकारी केवल वेबसाइट https://www.gerpegov.com/MOC और www.culturenorthindia.com पर ही उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर: **0175-2202918, 2211429** पर संपर्क कर सकते है।

निदेशक
(उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र, पटियाला)

पाकिस्तान को निरंतर समर्थन देता रहेगा चीन

इस्लामाबाद, 26 मार्च (प.स.): चीन के राजदूत जियांग जेदोंग ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि चीन पाकिस्तान में व्यापार व निवेश के लिए निरंतर समर्थन देता रहेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक में उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस्हाक डार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान जियांग ने पाकिस्तान की 'आर्थिक स्थिरता' की सराहना की। प्रधानमंत्री शरीफ ने चीन की ओर से निरंतर मिलने वाले आर्थिक समर्थन की सराहना करते हुए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई कि वह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को आगे बढ़ाते हुए कृषि, औद्योगिक सहयोग और प्राथमिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।

जियांग ने पाकिस्तान की आर्थिक मजबूती और सुधार के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए विशेष रूप से व्यापार और निवेश के क्षेत्र में चीन के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उच्च-स्तरीय बैठकों की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री शरीफ ने क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा करते हुए पश्चिम एशिया में तनाव कम करने में पाकिस्तान की रचनात्मक भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने आपसी हित के मुद्दों पर सभी स्तरों पर करीबी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
शाखा : सैक्टर-13 करनाल हरियाणा,
ईमेल: dbkarn@bankofbaroda.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

चल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना "परिशिष्ट-IV-A [नियम 6 (2) और 8 (6) के परंतुक देखें]

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 6 (2) एवं 8 (6) के परंतुक के अंतर्गत चल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/बंधक है और जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसी है, जहां है", "जैसी है वैसी है" और "जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर बेची जाएगी। ऋण लेने वाले/गिरवी रखने वाले/गारंटर/सुरक्षित संपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र./लॉट सं.	ऋण लेने वाले/वाले/गारंटर/गिरवीदार का नाम और पता	चल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण दीजिए, यदि कोई ज्ञात भार हो तो उसका भी उल्लेख कीजिए (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति, लघु एवं मध्यम उद्यम कुंडली)।	कुल देय राशि (रु. में) (बकाया राशि + अवैतनिक ब्याज + अप्रयुक्त ब्याज + लागू शुल्क सहित) 24.03.2026 तक	1) ईएमडी जमा खाता संख्या 2) आईएफएससी कोड 3) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा 4) स्वामित्व की स्थिति	1) ई-नीलामी की तिथि 2) ई-नीलामी का समय (समाप्ति का समय)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	1. आरक्षित मूल्य - संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय 2. बयाना राशि जमा (ईएमडी) 3. बोली वृद्धि राशि
01	श्री रजत कुमार पुत्र सुभाष कुमार, वीपीओ कुटैल, तहसील घरौंडा, जिला करनाल	मारुति सुजुकी [illegible] रखा जाय - पंजीकरण संख्या [illegible]; इंजन संख्या: [illegible], चैसिस संख्या: [illegible], वाहन का रंग: [illegible] आर्थिक ब्याहट, मालिक का नाम: श्री रजत कुमार, पुत्र सुभाष कुमार	11,48,793.77 रुपए (ग्यारह लाख अड़तालीस हजार सात सौ तिरानवे और सतहत्तर पैसे मात्र) साथ ही 25-03-2026 से प्रभावी अप्रयुक्त ब्याज और अन्य शुल्क।	1) 96290015181869 2) बीएआरबीओडीबीकेएआरएन 3) बैंक ऑफ बड़ौदा, सैक्टर-13, करनाल, हरियाणा 132001 4) भौतिक	1) 22.04.2026 2) दोपहर 02.00 बजे से सायं 6.00 बजे	15.04.2026 से 21.04.2026 तक (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक पूर्व नियुक्ति के बिना [illegible]	1) रु. 8,55,000.00 (जीएसटी सहित) 2) रु. 85,500.00 3) रु. 20,000.00

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया वैबसाइट https://www.bankofbaroda.in/e-auction और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल Baanknet.com देखें। इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर +91-8398000917 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 26.03.2026 स्थान : करनाल अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा